

## भारत: ILO के शाषी नकिय क अड्यकष

### प्रलिमिस के लयि

अंतरराषट्रीय शरु संगठन, ILO शाषी नकिय, ILO के प्रमुख अभसिमय

### मेन्स के लयि

भारत और अंतरराषट्रीय शरु संगठन

## चरुा में कयों?

भारत और अंतरराषट्रीय शरु संगठन (International Labour Organization-ILO) के बीच 100 वर्षों के उपयोगी संबंघों के एक नए अध्याय को चहिनति करते हुए भारत ने 35 वर्षों बाद [अंतरराषट्रीय शरु संगठन](#) के शाषी नकिय की अध्याकषता ग्रहण की है।

## प्रमुख बडि

- शरु और रोजगार सचवि **अपूर्वा चंद्रा** को **अक्टूबर 2020 से जून 2021** तक की अवधि के लयि ILO के शाषी नकिय का अध्याकष चुना गया है।
- ILO के शाषी नकिय के अध्याकष का पद **अंतरराषट्रीय स्तर के महत्त्व का पद** है। शाषी नकिय (Governing Body- GB) **ILO का शीरष कार्यकारी नकिय** है।
  - शाषी नकिय की बैठकें वर्ष में तीन बार मार्च, जून और नवंबर में आयोजति की जाती हैं। यह ILO नीतिपर नरिणय लेता है, अंतरराषट्रीय शरु सम्मेलन के लयि एजेंडा नरिधारति करता है, सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत करने के लयि कार्यक्रम प्रारूप तथा बजट को स्वीकार करता है तथा महानदिशक (Director-General) का चुनाव करता है।
  - ILO की व्यापक नीतियों **अंतरराषट्रीय शरु सम्मेलन** के माध्यम से नरिधारति की जाती हैं जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष एक बार जून में स्विट्जरलैंड के जनिवा में कयि जाता है। इसे प्रायः **अंतरराषट्रीय शरु संसद** के रूप में संदर्भति कयि जाता है।
- अपूर्वा चंद्रा शाषी नकिय की आगामी बैठक की अध्याकषता करेंगे जिसका आयोजन नवंबर 2020 में कयि जाएगा।
  - यह संगठति अथवा असंगठति कषेत्र के सभी शरुमकों को सामाजकि सुरकषा के सार्वभौमकिरण के संबंघ में धारणा स्पष्ट करने के अलावा शरु बाजार की कठोरता को दूर करने के लयि सरकार द्वारा की गई परिवर्तनकारी पहलों से प्रतभिगयिों को अवगत कराने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।
  - मजदूरी, औद्योगकि संबंघ, सामाजकि एवं व्यावसायकि सुरकषा, स्वास्थय एवं कार्य स्थति से संबंघति चार संहतिओं से यह अपेकषा की जा सकती है कवि शरुमकों के हतियों की रकषा कर सकती है तथा व्यवसाय संचालन को सरल बनाकर उसमें सुधार कर सकती है।
    - हाल ही में भारतीय संसद ने औद्योगकि संबंघों, व्यावसायकि सुरकषा, स्वास्थय एवं कार्य स्थति और सामाजकि सुरकषा पर **तीन शरु संहति** पारति की हैं जो देश के पुरातन शरु कानूनों को सरल बनाने और शरुमकों के लाभों से समझौता कयि बना आर्थकि गतविधियिों को गति देने के लयि प्रस्तावति हैं।

## अंतरराषट्रीय शरु संगठन (ILO)

- यह संयुक्त राषट्र की एकमात्र त्रपिकषीय संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधिद्वारा राषट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी।
- यह शरु मानक नरिधारति करने, नीतियिों वकिसति करने एवं सभी महलिओं तथा पुरुषों के लयि सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नयिोकताओं और शरुमकों को एक साथ लाता है।
- वर्ष 1946 में ILO, संयुक्त राषट्र से संबद्ध पहली वशिषिट एजेंसी बना।
- ILO में कार्रवाई का मुख्य साधन अभसिमयों एवं समझौतों के रूप में अंतरराषट्रीय शरु मानकों की स्थापना करना है।
  - अभसिमय अंतरराषट्रीय संधियिों और ऐसे उपकरण हैं, जो उन देशों के लयि कानूनी रूप से बाध्यकारी दायतियों का नरिमाण करते हैं जनिके द्वारा इनकी पुषटि की जाती है।

- इसकी अनुशंसाएँ गैर-बाध्यकारी हैं और राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यों को उन्मुख करने वाले दशा-नरिदेशों का नरिधारण करती हैं ।
- वर्ष 1969 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- यह वार्षिक [वशिव रोजगार और सामाजिक दृषटकिण](#) (World Employment and Social Outlook- WESO) रुझान रपौरट जारी करता है ।

## भारत और ILO:

- भारत, ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के शाषी नकिया का स्थायी सदस्य रहा है । भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में शुरु हुआ था ।
- भारत ने ILO के 41 अभसिमयों की पुषटकी है, जो कई अन्य देशों में मौजूद स्थतिकी तुलना में कहीं अधिक बेहतर है ।
- भारत ने आठ प्रमुख/मौलिक ILO अभसिमयों में से 6 की पुषटकी है । ये अभसिमय नमिनलखिति हैं:
  - बलात् श्रम पर अभसिमय (संख्या 29)
  - बलात् श्रम के उनमूलन पर अभसिमय (संख्या 105)
  - समान पारश्रमकि पर अभसिमय (संख्या 100)
  - भेदभाव (रोज़गार और व्यवसाय) पर अभसिमय (संख्या 111)
  - न्यूनतम आयु पर अभसिमय (संख्या 138)
  - बाल श्रम के सबसे वकित स्वरूप पर अभसिमय (संख्या 182)
- भारत ने दो प्रमुख/मौलिक अभसिमयों, अर्थात् संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठति होने के अधिकार की सुरक्षा पर अभसिमय, 1948 (संख्या 87) और संगठति एवं सामूहिक सौदेबाज़ी के अधिकार पर अभसिमय, 1949 (संख्या 98) की पुषटकि नहीं की है ।
  - ILO की कन्वेंशन संख्या 87 एवं 98 की पुषटकि नहीं करने का मुख्य कारण सरकारी करमचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतबिंध हैं ।
- ILO ने कोवडि-19 के प्रकोप के कारण धीमी पड़ चुकी आर्थिक गतविधियों को बढावा देने के लयि कई भारतीय राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में कयि गए परविरतनों पर गहरी चति व्यक्त की है ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-assumes-the-chairmanship-of-the-governing-body-of-ilo>

